इनोवेशन से सशक्त होगा फार्मा उद्योग

मंत्री गोयल ने कहा—सरकार किफायती स्वास्थ्य सेवाओं के लक्ष्य के साथ फार्मा इकोसिस्टम तैयार करने हेतु प्रतिबद्ध

नई दिल्ली, 28 जुलाई भारत को वैश्विक स्तर पर नवाचार आधारित फार्मास्युटिकल महाशक्ति बनाने की दिशा में केंद्र सरकार लगातार प्रयासरत है. केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने स्पष्ट किया है कि सरकार का लक्ष्य ऐसा फार्मा इकोसिस्टम तैयार करना है, जो अनुसंधान, नवाचार और आधुनिक उपचार तकनीकों को बढ़ावा देने के साथ-साथ देश और दुनिया के लोगों को किफायती स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध कराए.

उन्होंने कहा कि भारत का फार्मास्युटिकल उद्योग पहले से ही दुनिया के सबसे बड़े उद्योगों में शामिल है और अब इसे इनोवेशन आधारित वैश्विक नेतृत्व की ओर आगे बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि उन्होंने इंडियन फार्मास्युटिकल अलायंस के प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तृत और सार्थक चर्चा की. इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व आईपीए के अध्यक्ष डॉ. शारविल पटेल ने किया. बैठक में भारत के फार्मा क्षेत्र को अनुसंधान एवं विकास , क्लीनिकल रिसर्च और एडवांस्ड थेरेपी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए रणनीतियों पर विचार-विमर्श हुआ. बैठक के दौरान इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि सरकार और उद्योग के बीच मजबूत साझेदारी से भारत में नवाचार को नई गति मिल सकती है.

भारत का फार्मास्युटिकल उद्योग लंबे समय से दुनिया के कई देशों को किफायती जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति कर रहा है. यही कारण है कि भारतीय दवा उद्योग को वैश्विक स्वास्थ्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है. सरकार भी उत्पादन क्षमता बढ़ाने, घरेलू विनिर्माण को मजबूत करने और नई दवाओं के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न योजनाओं और नीतिगत सुधारों पर काम कर रही है. इससे भारत न केवल विनिर्माण केंद्र के रूप में बल्कि नवाचार आधारित फार्मा हब के रूप में भी अपनी पहचान मजबूत कर सकेगा.

कच्चे तेल में नरमी से 54 पैसे मजबूत हुआ रुपया

मुंबई, 28 जुलाई वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल में गिरावट से रुपया 54 पैसे मजबूत हुआ और कारोबार की समाप्ति पर एक डॉलर 95.99 रुपये का बोला गया. अमेरिका के ईरान पर हमले रोकने से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल आज फिसल गया. लंदन का ब्रेंट क्रूड वायदा 6.5 फीसदी टूटकर 90.50 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया. इससे रुपये को समर्थन मिला. भारतीय मुद्रा लगातार दूसरे दिन मजबूत हुई है. पिछले कारोबारी दिवस पर यह 20 पैसे की बढ़त में 96.53 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुई थी. रुपया आज 35 पैसे ऊपर 96.18 रुपये प्रति डॉलर पर खुला. दिन भर इसमें बड़ा उतार-चढ़ाव देखा गया. यह नीचे 96.27 रुपये और ऊपर 95.79 रुपये प्रति डॉलर तक जाने के बाद अंत में 95.99 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ.

ट्रंप टैरिफ से बढ़ीं निर्यात की चुनौतियां

अमेरिका के नए टैरिफ नियमों में भारत को राहत तो मिली

अमेरिका को 25% भारतीय निर्यात पर लागत बढ़ने का दबाव बरकरार

नई दिल्ली, 28 जुलाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ नीति ने भारत के निर्यात क्षेत्र के सामने अवसर और चुनौती दोनों खड़े कर दिए हैं. एक ओर भारत को कई प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में कम टैरिफ का लाभ मिला है, जिससे कुछ निर्यात क्षेत्रों के लिए अमेरिकी बाजार में संभावनाएं बढ़ी हैं.

वहीं दूसरी ओर अमेरिका को होने वाले भारत के लगभग 25 प्रतिशत निर्यात पर अब भी लागत बढ़ने का दबाव बना हुआ है. ऐसे में यह नई नीति भारतीय निर्यातकों के लिए राहत और जोखिम का मिला-जुला संकेत मानी जा रही है.अमेरिका ने यह नया टैरिफ ट्रेड एक्ट, 1974 की धारा 301 के तहत लागू किया है. अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (यूएसटीआर) ने करीब 60 देशों की समीक्षा कर यह आकलन किया कि वे बंधुआ मजदूरी से बने उत्पादों के आयात को रोकने के लिए कितने प्रभावी कदम उठा रहे हैं. इसी आधार पर अलग-अलग देशों के लिए नई टैरिफ दरें निर्धारित की गईं. इन नई दरों की घोषणा 23 जुलाई 2026 को की गई और 24 जुलाई से इन्हें लागू कर दिया गया. शुरुआत में भारत को 12.5 प्रतिशत टैरिफ श्रेणी में रखा जाना प्रस्तावित था.

विशेषज्ञों का मानना है कि इसका सबसे अधिक लाभ टेक्सटाइल, फार्मास्युटिकल, इंजीनियरिंग सामान और कुछ विनिर्माण क्षेत्रों को मिल सकता है. इसके बावजूद पूरी तस्वीर सकारात्मक नहीं है. विश्लेषण के अनुसार, अमेरिका को होने वाले भारत के लगभग 25 प्रतिशत निर्यात पर अब भी अतिरिक्त लागत का दबाव बना रहेगा. अलग-अलग उत्पादों पर लागू विशेष शुल्क और सीमित राहत के कारण कई भारतीय निर्यातकों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता प्रभावित हो सकती है.

स्टेफ्री ने पेश किया नया स्टेफ्री सिक्योर एक्सएल पैड

नवभारत, जबलपुर। भारत के अग्रणी मेंस्ट्रुअल हाइजीन ब्रांड स्टेफ्री ने महिलाओं की पीरियड्स के दौरान लीकेज और बार-बार पैड बदलने की चिंता को दूर करने के लिए नया 'स्टेफ्री सिक्योर एक्सएल' पेश किया है। इस मौके पर स्टेफ्री इंडिया की मार्केटिंग डायरेक्टर सुप्रिया श्रीनिवास ने बताया कि यह उत्पाद पैड चेंज अलर्ट फीचर और पेटेंटेड लीक लॉक टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जो बारह घंटे तक सुरक्षा प्रदान करता है। इस नए उत्पाद के बाजार में आने से महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान होने वाले मानसिक तनाव और बार-बार पैड चेक करने की परेशानी से बड़ी राहत मिलेगी।

अत्याधुनिक तकनीक से मिलेगा बेहतर कम्फर्ट- इस दौरान केन्व्यू के बेबी एंड वीमेंस हेल्थ रिसर्च एंड डेवलपमेंट हेड डॉ. दिलीप त्रिपाठी ने कहा कि विस्तृत रिसर्च के आधार पर तैयार किया गया यह नया इनोवेशन पीरियड्स के दौरान महिलाओं को सुरक्षा के साथ बेहतर कम्फर्ट और आत्मविश्वास देगा। ब्रांड ने इस उत्पाद के प्रचार के लिए एक नया मार्केटिंग कैम्पेन और टेलीविजन एड भी शुरू किया है, जिसमें बॉलीवुड अभिनेत्री और ब्रांड एंबेसडर कियारा आडवाणी दिखाई दे रही हैं और इसका निर्देशन मशहूर फिल्म डायरेक्टर शूजित सरकार ने किया है।

जियो ने जोड़े सबसे ज्यादा सक्रिय ग्राहक

जून में जियो ने 33.3 लाख सक्रिय मोबाइल ग्राहक जोड़े.

5जी एफडब्ल्यूए और वायरलाइन सेवाओं में भी जियो पहले स्थान पर

नई दिल्ली, 28 जुलाई जून 2026 में सक्रिय मोबाइल ग्राहकों की दौड़ में रिलायंस जियो सबसे आगे रहा. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के आंकड़ों के मुताबिक कंपनी ने महीने के दौरान 33.3 लाख सक्रिय यानी वीएलआर (विजिटर लोकेशन रजिस्टर) ग्राहक जोड़े.

इसके साथ ही जियो का सक्रिय मोबाइल ग्राहक आधार बढ़कर 49.89 करोड़ हो गया. देश के कुल 120.11 करोड़ सक्रिय मोबाइल ग्राहकों में जियो की हिस्सेदारी करीब 41.5 प्रतिशत दर्ज की गई. ट्राई के आंकड़ों के अनुसार, जून महीने में जियो ने कुल 21.5 लाख नए मोबाइल ग्राहक भी जोड़े, जिससे उसका कुल मोबाइल ग्राहक आधार बढ़कर 50.36 करोड़ हो गया. 39.3 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी के साथ कंपनी देश की सबसे बड़ी मोबाइल सेवा प्रदाता बनी हुई है. सक्रिय ग्राहकों के मामले में भारती एयरटेल ने 29.3 लाख नए ग्राहक जोड़े, जबकि वोडाफोन आइडिया, बीएसएनएल और एमटीएनएल के सक्रिय ग्राहक आधार में गिरावट दर्ज की गई. फिक्स्ड लाइन सेवाओं में भी रिलायंस जियो पहले स्थान पर रही. जून के दौरान कंपनी ने करीब 1.44 लाख नए वायरलाइन कनेक्शन जोड़े, जिससे उसके कुल वायरलाइन ग्राहकों की संख्या बढ़कर 1.56 करोड़ हो गई. इस श्रेणी में कंपनी की बाजार हिस्सेदारी 32.7 प्रतिशत रही, जो इसे इस क्षेत्र का सबसे बड़ा सेवा प्रदाता बनाती है.

5जी फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस (एफडब्ल्यूए) सेवाओं में भी जियो का दबदबा कायम रहा. जून के अंत तक कंपनी के 5जी एफडब्ल्यूए ग्राहकों की संख्या बढ़कर 91.14 लाख पहुंच गई, जो देश के कुल 5जी एफडब्ल्यूए ग्राहकों का 70.5 प्रतिशत है. कंपनी ने जून महीने में करीब 1.46 लाख नए 5जी एफडब्ल्यूए ग्राहक जोड़े. इसके अलावा, यूबीआर आधारित फिक्स्ड वायरलेस सेवा उपलब्ध कराने वाली जियो देश की एकमात्र कंपनी बनी हुई है और इस सेवा के ग्राहकों की संख्या बढ़कर 49.34 लाख हो गई है. ट्राई के मुताबिक जून 2026 के अंत तक देश का कुल टेलीफोन ग्राहक आधार बढ़कर करीब 134.8 करोड़ हो गया.

एचडीएफसी बैंक ने अधिकारियों पर की सख्त कार्रवाई

मुंबई, 28 जुलाई देश के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंक एचडीएफसी बैंक के निदेशक मंडल ने आंतरिक जांच के बाद अपने ही शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशिधर जगदीशन, मुख्य वित्तीय अधिकारी श्रीनिवासन वैद्यनाथन तथा रिटेल एसेट्स के ग्रुप हेड अरविंद वोहरा पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

इसके साथ ही तीनों अधिकारियों को चेतावनी पत्र भी जारी किए गए हैं. बैंक ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम के साथ हुए डिपॉजिट समझौतों की आंतरिक समीक्षा के आधार पर की गई है. बैंक की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, यह मामला वर्ष 2017 और 2021 में एमएसआरडीसी से जमा राशि जुटाने के लिए किए गए समझौतों से जुड़ा है. इन समझौतों की जांच बैंक के स्वतंत्र निदेशकों की एक विशेष अनुशासनात्मक समिति ने की. समिति की रिपोर्ट और सिफारिशों पर 23 जुलाई 2026 को हुई बोर्ड बैठक में विस्तार से विचार किया गया, जिसके बाद संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्णय लिया गया.

गंगा एक्सप्रेसवे लंबाई और असर में आगे

594 किमी लंबा गंगा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे से साढ़े तीन गुना बड़ा

नई दिल्ली, 28 जुलाई उत्तर प्रदेश में तेजी से विकसित हो रहे एक्सप्रेसवे नेटवर्क ने राज्य की कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को नई दिशा दी है.

एक ओर वर्ष 2012 से संचालित यमुना एक्सप्रेसवे ने दिल्ली-एनसीआर और आगरा के बीच यात्रा को तेज और सुविधाजनक बनाया है, वहीं दूसरी ओर गंगा एक्सप्रेसवे राज्य के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों को जोड़ने वाला सबसे महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा परियोजना बनकर उभरा है. दोनों एक्सप्रेसवे अपनी-अपनी भूमिका में महत्वपूर्ण हैं, लेकिन लंबाई, आर्थिक प्रभाव, यात्रा समय और विकास की संभावनाओं के लिहाज से गंगा एक्सप्रेसवे अधिक व्यापक परियोजना माना जा रहा है. लंबाई की दृष्टि से गंगा एक्सप्रेसवे स्पष्ट रूप से आगे है. इसकी कुल लंबाई 594 किलोमीटर है, जबकि यमुना एक्सप्रेसवे 165.5 किलोमीटर लंबा है. यानी गंगा एक्सप्रेसवे यमुना एक्सप्रेसवे से लगभग साढ़े तीन गुना बड़ा है. यह मेरठ से शुरू होकर प्रयागराज तक जाता है और पश्चिमी तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई प्रमुख जिलों को आपस में जोड़ता है. दूसरी ओर यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ते हुए दिल्ली-एनसीआर, मथुरा और आगरा के बीच तेज संपर्क उपलब्ध कराता है.दोनों एक्सप्रेसवे का उद्देश्य भी अलग-अलग है.

एयू बैंक ने बढ़ाई एनआरआई जमा ब्याज दरें

मुंबई , 28 जुलाई एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एफसीएनआर (बी) जमा (विदेशी मुद्रा अनिवासी बैंक खातों में जमा) पर अधिकतम ब्याज की दर 7.10 प्रतिशत वार्षिक से बढ़ाकर 7.40 प्रतिशत कर दिया है.बैंक की सोमवार को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार यह दर 3 से 4 वर्ष की अवधि वाले जमा पर लागू होगी. वहीं, एनआरई -डिपॉजिट में जमा पर अधिकतम ब्याज दर 7.00 प्रतिशत प्रति वर्ष से बढ़ाकर 7.60 प्रतिशत प्रति वर्ष कर दी गई है, जो 36 महीने 1 दिन से 45 महीने की अवधि वाले जमा पर लागू होगी.

समय पर मिला बीमा का पैसा

मुंबई, 28 जुलाई. जीवन बीमा की असली अहमियत तब समझ आती है, जब मुश्किल समय में परिवार को बिना भागदौड़ और बिना देरी के पैसा मिल जाए.

यही भरोसा मजबूत करने की दिशा में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में अपने ग्राहकों को 4,666 करोड़ रुपए के क्लेम और मैच्योरिटी का भुगतान किया.इस दौरान, कंपनी ने 1,306 करोड़ रुपए मृत्यु दावों के तहत और 3,360 करोड़ रुपए मैच्योरिटी व सर्वाइवल बेनेफिट्स के रूप में दिए. कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 99.3% रहा. वहीं, जिन दावों में जाँच की जरूरत नहीं थी, उनका भुगतान औसतन एक दिन में कर दिया गया. पहली तिमाही में कंपनी का शुद्ध मुनाफा 27.8% बढ़कर 386 करोड़ रुपए रहा. वहीं, टर्म प्लान (रिटेल प्रोटेक्शन) कारोबार में 60.4% की बढ़त दर्ज की गई. कंपनी के बोर्ड ने नाम बदलकर आईसीआईसीआई लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है. हालाँकि, इसके लिए नियामकीय मंजूरी मिलना बाकी है.

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के एमडी एवं सीईओ अनुप बागची ने कहा, 'ग्राहक हमेशा हमारी पहली प्राथमिकता रहे हैं. 99.3% क्लेम सेटलमेंट रेशियो और बिना जाँच वाले दावों का एक दिन में भुगतान इस बात का सबूत है कि जरूरत के समय हम अपने ग्राहकों के साथ खड़े हैं.' उन्होंने कहा कि कंपनी आगे भी एआई और डिजिटल तकनीक के जरिए सेवाओं को और आसान बनाएगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बेहतर और तेज बीमा सेवाएँ पहुँच सकें

समाचार विशेष

भाजपा, राजद और प्रशांत किशोर की मुश्किल?

बांकीपुर के इन इलाकों ने बढ़ाई सबके सामने चुनौती

पटना. बिहार की राजधानी पटना स्थित बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में मतदान के लिए अब सिर्फ पांच दिन बचे हैं. जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है इस सीट की राजनीतिक लड़ाई 50 बूथों पर केंद्रित हो गई है. इन बूथों पर प्रत्येक में करीब 1,000 से 1,250 मतदाता हैं.

यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के प्रत्याशी नीरज सिन्हा, महागठबंधन से राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार रेखा गुप्ता, और जनसुराज के प्रशांत कुमार ने इन बूथों पर अपनी पूरी ताकत लगा रही है. सभी की कोशिश है कि मतदान वाले दिन यहां बड़ी संख्या में वोटर्स पहुंचे. बांकीपुर पूरी तरह शहरी सीट है और यहां मतदान प्रतिशत परंपरागत रूप से अपेक्षाकृत कम रहता है. कई बड़े बूथों पर एक हजार से अधिक मतदाता होने के बावजूद मतदान 50 प्रतिशत से भी नीचे रहता है. अब जबकि यह उपचुनाव है ऐसे में मतदान और कम होने के आसार हैं. बांकीपुर विधानसभा की चुनावी लड़ाई अब चार सबसे बड़े चुनावी क्षेत्रों पर सिमट गई है. इनमें कदमकुआं सबसे बड़ा क्षेत्र है, जहां 58 बूथों पर 50,780 मतदाता हैं. इसके बाद बोरिंग रोड-श्रीकृष्णपुरी-राजापुर में 56 बूथों पर करीब 50 हजार मतदाता, भंवर पोखर-दरियापुर-अशोक राजपथ में 44 बूथों पर 38,995 मतदाता और जक्कनपुर-पुरंदरपुर में 39 बूथों पर 34,005 मतदाता हैं.

कम मतदान बना सबसे बड़ी चुनौती

बांकीपुर में कुल 422 बूथ हैं. 2 जुलाई को उपचुनाव की घोषणा हुई थी और 6 जुलाई को अधिसूचना जारी हुई. कई उम्मीदवारों ने 13 जुलाई को नामांकन के अंतिम दिन पर्चा दाखिल किया, जिससे प्रभावी चुनाव प्रचार के लिए केवल 15 दिन का समय मिला. कम समय और शहरी मतदाताओं की उदासीनता को देखते हुए सभी प्रमुख दलों ने अपने संगठन, बूथ प्रबंधन और जनसंपर्क अभियान का सबसे बड़ा हिस्सा इन चार प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित कर दिया है.

जदयू का विरोध कहां तक जाएगा?

पटना. यह बड़ा सवाल है कि बिहार सरकार में शामिल और लगभग बराबर की भूमिका निभा रही जनता दल यू अगर अपनी ही सरकार के फैसलों का विरोध जारी रखती है तो वह इसे लेकर कहां तक जा सकती है?

जदयू ने शिक्षा में हो रहे बदलावों से जुड़े दो फैसलों का विरोध किया है. पहला फैसला तो डिग्री कॉलेज और पीजी कॉलेज अलग करने और डिग्री कॉलेजों को सीधे सरकार के शिक्षा विभाग के अधीन लाने के प्रस्ताव का है. इसका विरोध तो भाजपा के भी कुछ विधायकों और अन्य नेताओं ने किया है. पटना से लेकर दिल्ली तक अलग अलग विश्वविद्यालयों के शिक्षकों ने भी इसका विरोध किया है. दूसरा मामला राज्य के मॉडल स्कूलों का नाम और रंग बदलने का है.

राज्य सरकार ने तय किया है कि साढ़े पांच सौ स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाया जाएगा. इनका नाम सरस्वती विद्या निकेतन रखा गया है. यह फैसला किया गया है इन स्कूलों का रंग बदला जाएगा. इन्हें भगवा रंग में रंगने का निर्देश दिया गया है. जदयू नेताओं ने सरस्वती विद्या निकेतन को भाजपा के सरस्वती शिशु मंदिर से तो नहीं जोड़ा है लेकिन रंग को लेकर आपत्ति जताई है.

भाजपा में प्रभारियों की नियुक्ति पर मंथन

लखनऊ. चुनावी तैयारियों में जुटी भाजपा संगठन को संवारने में जुटी है. प्रदेश के सभी छह क्षेत्रों में अध्यक्ष बनाए गए हैं जहां अब सबकी नजर क्षेत्रीय प्रभारियों पर टिकी है. यह पद चुनावी दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होता है.

पीडीए की काट के लिए यहां भी जातीय समीकरणों की गणित सजाने की तैयारी है. भाजपा ने उत्तर प्रदेश को छह क्षेत्रों काशी, गोरखपुर, अवध, कानपुर, ब्रज एवं पश्चिम क्षेत्र में बांटा हैं जिसमें संगठनात्मक दृष्टि से 98 जिले हैं. 2023 के बाद भाजपा ने सभी छह क्षेत्रों में नए चेहरों को अध्यक्ष बनाया है. भाजपा ज्यादातर महामंत्रियों को क्षेत्रीय प्रभारी बनाती है. पिछली बार इसका अपवाद तब सामने आया जब प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष सिंह को ब्रज का प्रभारी बनाया गया. 71 विधानसभा सीटों वाले पश्चिम क्षेत्र में पिछली बार सतेंद्र सिसौदिया क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं संत कबीरनगर निवासी सुभाष यदुवंश क्षेत्रीय प्रभारी बनाए गए. उनसे पहले जेपीएस राठौर और विजय बहादुर पाठक क्षेत्रीय प्रभारी रहे. तीनों ही चेहरे पूर्वांचल या मध्य क्षेत्र से आते हैं. लेकिन इस बार चर्चा है कि गुर्जर क्षेत्रीय अध्यक्ष के सामने जाट समीकरण ठीक करने के लिए प्रदेश महामंत्री ब्रज क्षेत्र के राजेश चौधरी को प्रभारी बनाया जा सकता है. हालांकि पश्चिम के लिए आगरा के राम प्रताप सिंह एवं लखनऊ के अभिजात मिश्रा का भी नाम चर्चा में है. 65 विधान सभा सीटों वाले ब्रज क्षेत्र में संतोष सिंह, गोविंद नारायण शुक्ल, अशोक कटारिया, अश्विनी त्यागी प्रभारी रह चुके हैं, जहां इस बार वाराणसी के दिलीप पटेल, एवं गीता शाक्य का नाम चर्चा में है.

काशी क्षेत्र में खेला जा सकता है सवर्ण कार्ड

71 विधानसभा सीटों वाले काशी क्षेत्र में अमरपाल मौर्य, गोविंद नारायण शुक्ला प्रभारी रहे हैं, जहां इस बार ओबीसी क्षेत्रीय अध्यक्ष देखते हुए सवर्ण कार्ड खेला जा सकता है. 82 विधान सभा सीटों वाले अवध क्षेत्र में संजय राय एवं अमरपाल मौर्य क्षेत्रीय प्रभारी रहे हैं, जहां इस बार गीता शाक्य और राम प्रताप सिंह का नाम भी चर्चा में है. 52 विधानसभा सीटों वाले कानपुर क्षेत्र में अनूप गुप्ता, प्रियंका रावत एवं विजय बहादुर पाठक क्षेत्रीय प्रभारी रहे हैं, जहां ब्राह्मण फैक्टर साधने के लिए अभिजात मिश्रा के नाम पर भी विचार हो रहा है. 62 विधान सभा सीटों वाले गोरखपुर क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की बड़ी आबादी है, जहां पूर्व सांसद एवं प्रदेश महामंत्री उपेंद्र रावत और शंकर लाल लोधी का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है.

विशेष | **दक्षिण हरियाणा भाजपा में नहीं थम रही गुटबाजी**

बयानों से फिर उभरी अंदरूनी खींचतान

चंडीगढ़. दक्षिण हरियाणा में भाजपा की अंदरूनी गुटबाजी एक बार फिर खुलकर सामने आती दिख रही है. पिछले कुछ समय से केंद्रीय राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह के समर्थक खेमे और पूर्व मंत्री डॉ.अभय सिंह यादव व वरिष्ठ नेता राव नरबीर सिंह के बीच लगातार बयानबाजी हो रही है.

यह टकराव अब केवल संगठन के भीतर की चर्चा नहीं रह गया, बल्कि सार्वजनिक मंचों पर भी दिखाई देने लगा है. रेवाड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के दौरान सामने आए घटनाक्रम ने इन राजनीतिक मतभेदों को और स्पष्ट कर दिया. मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन समारोह में पूर्व मंत्री अभय सिंह यादव ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि उनकी स्थिति उस पिता जैसी हो गई है, जिसने बेटी को पाल-पोसकर बड़ा किया, लेकिन कन्यादान के समय उसे ही दूर कर दिया गया. दरअसल वे कहना चाहते थे कि कोरियावास मेडिकल कॉलेज को लेकर उन्होंने खूब दौड़ भाग की मगर उसके उद्घाटन का श्रेय किसी दूसरे के पास चला गया. इसके जवाब में मंत्री आरती राव ने भी बिना नाम लिए कहा कि किसी एक व्यक्ति के होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता. दोनों नेताओं के ये बयान यह संकेत देने के लिए काफी हैं कि दक्षिण हरियाणा भाजपा में रिश्ते सहज नहीं हैं. हालांकि दोनों खेमे के बीच पहले भी इस तरह की बयानबाजी चलती रही है.

इससे पहले रेवाड़ी में आयोजित खेत बचाओ अभियान का कार्यक्रम भी राजनीतिक चर्चा का केंद्र बन गया. केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जैसे बड़े नेताओं की मौजूदगी के बावजूद केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और जिले के तीनों भाजपा विधायक कार्यक्रम से दूर रहे. इतना ही नहीं, पार्टी के पांच मंडल अध्यक्षों ने भी इसमें भाग नहीं लिया. इतने बड़े स्तर पर स्थानीय नेतृत्व की गैरमौजूदगी को सामान्य राजनीतिक संयोग मानना मुश्किल है. इसी तरह जब जिला जनसंपर्क एवं कष्ट निवारण समितियों के प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति में भी आपसी गुटबाजी देखने को मिली थी. प्रदेश सरकार ने जिला जनसंपर्क एवं कष्ट निवारण समितियों के प्रभारी मंत्रियों की सूची जारी करते हुए राव नरबीर को रेवाड़ी और हांसी की जिम्मेदारी सौंपी थी. जब यह सूची बाहर आई तो इस पर केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत ने आपत्ति जता दी और कुछ ही घंटे बाद राव नरबीर को रेवाड़ी से हटाकर झज्जर में नियुक्त कर दिया था.

अलग-अलग शक्ति केंद्र

रेवाड़ी राव इंद्रजीत का गृह क्षेत्र है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि दक्षिण हरियाणा भाजपा लंबे समय से अलग-अलग शक्ति केंद्रों में बंटी हुई नजर आ रही है. चुनावी जीत के बावजूद स्थानीय नेताओं के बीच तालमेल की कमी समय-समय पर सामने आती रही है. सार्वजनिक मंचों पर दिए जा रहे बयान और कार्यक्रमों से दूरी यह संदेश दे रही है कि अंदरूनी असहमति अभी खत्म नहीं हुई है. हालांकि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व अब तक इन घटनाओं पर सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं बोला है, लेकिन यदि यह खींचतान लंबी चली तो इसका असर संगठन की एकजुटता और भविष्य की चुनावी रणनीति पर पड़ सकता है.